भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2541

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

इंडिया एनर्जी स्टैक

2541#. श्री अमर पाल मौर्यः

श्रीमती माया नारोलिया:

श्री बृज लाल:

श्री मिथलेश कुमार:

श्री मयंककुमार नायक:

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 'इंडिया एनर्जी स्टैक (आईईएस)' का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट के लिए चुनी गई विद्युत उपयोगिताओं सहित इंडिया एनर्जी स्टैक के पायलट कार्यान्वयन के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इंडिया एनर्जी स्टैक के चरणबद्ध राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए कोई ढांचा विकसित किया गया है;

(ड) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इंडिया एनर्जी स्टैक से विद्युत क्षेत्र में डिजिटलीकरण, अंतर-संचालनीयता और कार्यकुशलता में किस प्रकार सुधार होने की अपेक्षा है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ख) : इंडिया एनर्जी स्टैक (आईईएस) की परिकल्पना विद्युत क्षेत्र को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए की गई है ताकि विद्युत प्रणाली के विभिन्न हिस्सों को मानक डेटा विनिमय प्रोटोकॉल के माध्यम से सुरक्षित रूप से जुड़ने और संचार करने में सक्षम बनाया जा सके। विद्युत मंत्रालय ने आईईएस के घटकों और डिजाइन सहित एक रोडमैप तैयार करने के लिए मंत्रालयों, राज्य यूटिलिटी, विनियामकों,

जेनकोस और ट्रांसकोस के प्रतिनिधियों सहित डोमेन विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों से युक्त एक कार्य बल का गठन किया है।

दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मुंबई की वितरण यूटिलिटी को आईईएस के पायलट (प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट) कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किया गया है, और कार्यान्वयन चल रहा है।

आईईएस का उद्देश्य एक ऐसा एकीकृत, सुरक्षित और अंतर-संचालनीयता डेटा एक्सचेंज तंत्र विकसित करना है, जिससे विद्युत क्षेत्र की पूरी मूल्य शृंखला में सेवाएँ और तंत्र निर्बाध रूप से एक साथ काम कर सकें और अंतर-संचालनीयता में सुधार हो सके। आईईएस द्वारा तैयार समक्ष प्रणाली का उद्देश्य प्रोद्योगिकी समाधान को आसानी से एकीकृत करना है, जो वितरण क्षेत्र और उपभोक्ता-केन्द्रित सेवाएँ जैसे भार का पूर्वानुमान, मांग प्रतिक्रिया कार्यक्रम, ऊर्जा आदान-प्रदान की क्षमता बढ़ाने और विद्युत क्षेत्र में सम्पूर्ण डिजिटलीकरण में सहायता करते हैं।

****